जनसत्ता

राहत और चुनौती

पिछले दो महीने में दूसरी बार रेपो दर में कमी करके रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाने का संकेत दिया है। केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर में इस बार भी चौथाई फीसद की कटौती की है। इससे पहले फरवरी में भी इसमें इतनी ही कमी की गई थी। यों तो मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था के तमाम महत्त्वपूर्ण पक्षों को प्रभावित करती है, लेकिन आम लोगों को मौद्रिक नीति समीक्षा का इंतजार इसलिए रहता है कि इसी को आधार बना कर व्यावसायिक बैंक कर्ज की दरें तय करते हैं। जाहिर है, अगर रेपो रेट कम होती है तो व्यावसायिक बैंकों पर भी कर्ज सस्ता करने का दबाव होगा। हालांकि पिछले पूरे साल में रेपो दर को लेकर रिजर्व बैंक ने सख्त रुख अपनाया था। लेकिन पिछले तीन-चार महीने में हालात सुधरे हैं और महंगाई की दर चार फीसद से नीचे रही है। इसलिए रिजर्व बैंक ने रेपो दर कम कर आर्थिकी को रफ्तार देने की कोशिश की है।

मौद्रिक नीति समिति के चार सदस्यों ने रेपो दर कम करने, जबकि दो सदस्यों ने इसे स्थिर बनाए रखने के पक्ष मत दिया था। यह इस बात का संकेत माना जाना चाहिए कि अर्थव्यवस्था की भविष्य की चुनौतियों को लेकर केंद्रीय बैंक में कहीं न कहीं बड़ी चिंताएं भी शामिल हैं। भारत की अर्थव्यवस्था के संकेतक कोई उत्साहजनक तस्वीर पेश नहीं कर रहे हैं। केंद्रीय बैंक इस हकीकत को अच्छी तरह समझ रहा है। उद्योगों की दशा संतोषजनक नहीं है, औद्योगिक उत्पादन की रफ्तार सुस्त है, सेवा क्षेत्र से भी अच्छे नतीजे नहीं आ रहे, विमानन क्षेत्र संकट में है, निर्यातकों का दम फूल रहा है और सबसे बड़ी बात यह कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम स्थिर नहीं है। इसके अलावा मानसून और वित्तीय बाजार को लेकर बनी अनिश्चितता व राजकोषीय असंतुलन के खतरे को भी केंद्रीय बैंक भांप रहा है। इन सबका मिला-जुला असर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती बना हुआ है। इसीलिए मौद्रिक नीति समिति ने आर्थिक विकास दर के अनुमान को भी 7.4 से घटा कर 7.2 फीसद कर दिया है। कुछ महीनों से वैश्विक अर्थव्यवस्था में फिर से मंदी आने की आशंका व्यक्त की जा रही है। यह भारत के लिए भी गंभीर चिंता पैदा करने वाली है।

ऐसे में रिजर्व बैंक ने जो सधे हुए कदम उठाए हैं उनका पहला मकसद यही है कि व्यावसायिक बैंक कर्ज सस्ते करें, जिससे बाजार में पैसा आए और आर्थिकी का चक्र गति पकड़े। लेकिन व्यावसायिक बैंकों का रवैया हैरान करने वाला है। दरअसल, ये बैंक नीतिगत दरों में कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों को नहीं दे रहे हैं। इससे रिजर्व बैंक की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। फरवरी में केंद्रीय बैंक ने जब नीतिगत दरें घटाई थीं, तब ज्यादातर बैंकों ने अपने यहां ब्याज दरें नहीं घटाईं और कर्ज को महंगा बनाए रखा। जिन्होंने कटौती की भी तो नाममात्र की, जो ग्राहकों के लिए लाभ के रूप में बेअसर ही साबित हुई। बैंक इस कोशिश में लगे हैं कि वे रेपो दर में कटौती का लाभ ग्राहकों को देने के बजाय इसका फायदा अपनी लागत कम करने और एनपीए की भरपाई करने में उठा लें। ऐसे में रिजर्व बैंक को यह सुनिश्चित करना होगा कि नीतिगत दरों में कटौती का सीधा लाभ ग्राहकों को दिलवाने के बैंकों पर दबाव बनाए। वरना कर्ज के अभाव में छोटे और मझौले उद्योगों की सांस फूलती रहेगी। मकान, गाड़ी या अन्य जरूरतों के लिए कर्ज लेने वाले हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे, रियल एस्टेट की मंदी कई क्षेत्रों पर असर डालेगी।

शिक्षक का काम

देश भर में शिक्षा की सूरत पर होने वाली बहसों में यह सवाल सबसे प्रमुख रूप से उठता है कि चूंकि शिक्षकों को कई बार शिक्षकेतर कार्यों में उलझा दिया जाता है, इसलिए कक्षाओं की पढ़ाई-लिखाई प्रभावित होती है। लेकिन इसके उलट कुछ ऐसे मौके भी होते हैं जब शिक्षकों को शिक्षण से जुड़े कुछ कार्य-दायित्व सौंपे जाते हैं तो उसे जिम्मेदारी से पूरा करने के प्रति बहुत सारे शिक्षक उत्साह नहीं दिखाते हैं। इक्का-दुक्का मामलों को उदाहरण नहीं बनाया जा सकता, लेकिन यह उदासीनता कई बार ड्यूटी पूरा नहीं करने के रूप में सामने आती है। जाहिर है, यह कोई आदर्श तस्वीर नहीं है और इसके समाधान के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। इस तरह की स्थिति सीबीएसई यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सामने पैदा हुई, जब देश भर में परीक्षा के बाद उत्तर-पुस्तिका के मूल्यांकन के लिए बुलाए गए बहुत सारे शिक्षक ड्यूटी पर नहीं पहुंचे। खबर के मुताबिक सीबीएसई ने देश के अलग-अलग स्कूलों के साढ़े तीन हजार वैसे शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं जिन्होंने परीक्षा की उत्तर-पुस्तिका जांचने के लिए समय से मूल्यांकन केंद्र जाना जरूरी नहीं समझा। इनमें अकेले दिल्ली सरकार के स्कूलों के शिक्षकों की संख्या दो सौ से ज्यादा है। इसके अलावा, पंद्रह विद्यालयों को भी संबद्धता समाप्त करने के लिए नोटिस जारी किया गया है।

गौरतलब है कि उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कोई ऐसा काम नहीं है जिसे शिक्षकेतर कार्यों के रूप में देखा जा सके। यह शिक्षण और परीक्षा का एक अनिवार्य चरण है। जिस तरह कक्षाओं में पढ़ाना और परीक्षा लेना शैक्षणिक गतिविधियों में शामिल है, उसी तरह उत्तर-पुस्तिका की जांच भी इसी का हिस्सा है। इसलिए इस अहम चरण के लिए अगर किसी शिक्षक को दायित्व सौंपा जाता है तो ईमानदारी से उसका निर्वाह करने की भी उम्मीद की जाती है। लेकिन ऐसा अक्सर देखा जाता है जब कुछ शिक्षक अपनी ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतते हैं। हालांकि यह भी सच है कि ऐसी एक समूची व्यवस्था बन चुकी है जिसमें अपनी ड्यूटी की जिम्मेदारी को पूरा करने के लेकर बहुत सारे लोग गंभीर नहीं होते हैं। लेकिन ऐसे लोग शायद इस तथ्य से अनजान होते हैं कि इनकी उदासीनता या लापरवाही के चलते संबंधित विभाग या फिर उसकी जद में आने वाले लोगों के कार्यों के परिणामों पर कैसा विपरीत असर पड़ता है।

इसके बरक्स हमारे शिक्षा व्यवस्था की एक बड़ी सच्चाई यह है कि बहुतेरे ऐसे मौके आते हैं जब स्कूली शिक्षकों को शिक्षकेतर कार्यों को पूरा करने की ड्यूटी दे दी जाती है। जनगणना, चुनाव से संबंधित कार्य, समाज कल्याण से संबंधित कार्यों का सर्वेक्षण, पशुओं की गिनती या इस तरह के ऐसे कई कार्य हैं, जिनका शिक्षण से कोई वास्ता नहीं है। शिक्षकों को जब ऐसे कामों में उलझाया जाता है तो इसका शिक्षण पर नकारात्मक असर पड़ता है। यह बेवजह नहीं है कि स्कूली शिक्षा पर होने वाले अध्ययनों में पिछले कई सालों से यही स्थिति बनी हुई है कि बच्चों के सीखने का स्तर बेहद चिंताजनक है। यह तथ्य है कि स्कूलों में पहले ही भारी तादाद में शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं। शिक्षकों की पर्याप्त संख्या में नियुक्ति करने के बजाय जब सरकार मौजूदा शिक्षकों को ही शिक्षण के सिवा अन्य कार्यों में लगाती है तो शिक्षा की समग्र स्थिति पर इसके असर का अंदाजा लगाया जा सकता है। जरूरत इस बात की है कि शिक्षकों के खाली पदों पर नियुक्ति के साथ-साथ शैक्षणिक गतिविधियों के प्रति उन्हें जवाबदेह बनाने के लिए भी एक सुचिंतित व्यवस्था कायम की जाए, ताकि स्कूली शिक्षण के स्तर में गुणात्मक विकास किया जा सके।

कल्पमेधा

अगर इंसान परोपकारी नहीं है, तो उसमें
और दीवार पर बने चित्र में
क्या फर्क है।
– शेख़ सादी

आइएस का खात्मा और सवाल

संजीव पांडेय

सीरिया में आइएस राज खत्म किए जाने को लेकर दावे जरूर हैं। लेकिन अभी भी सच्चाई यह है कि हजारों लड़ाके सीरिया और इराक के दूरदराज इलाकों में चुपचाप बैठ गए हैं। चूंकि इराक में भी आइएस के खात्मे का दावा दिसंबर 2017 में किया गया था। लेकिन दस महीने में ही इराक में एक हजार से ज्यादा आतंकी हमले इराके में हुए। यही खतरा सीरिया में है।

सीरिया के लोगों के लिए यह खुशखबरी हो सकती है कि पूर्वी सीरिया के बगहोज क्षेत्र जो इस्लामिक स्टेट (आइएस) का अंतिम गढ़ था, उसे भी मुक्त करा लिया गया है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है। सीरिया के एक बड़े हिस्से के लोगों ने लंबे समय तक आइएस के क्रूर शासन को देखा। लेकिन अब सीरिया आइएस-मुक्त है। अगर इराक और सीरिया दोनों देशों के आइएस के कब्जे वाले इलाकों के क्षेत्रफल को देखा जाए तो यह ग्रेट ब्रिटेन के बराबर बैठता है। अमेरिका की वास्तविक मंशा सीरिया से राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार को हटाने की थी। लेकिन वहां पर रूस आड़े आ गया। अब अमेरिका आइएस के खात्मे का दावा कर ससम्मान सीरिया से बाहर निकलना चाहता है। हालांकि आइएस को सीरिया में खत्म किए जाने के दावे पर को लेकर तमाम सवाल हैं। उसके संभावित खतरे को खुद अमेरिकी स्वीकार कर रहे हैं। अमेरिकी सेना के मध्य कमान के प्रमुख जोसेफ वोटल ने भी भविष्य के इन खतरों को स्वीकार किया है। जोसेफ के अनुसार आइएस के गायब हुए कमांडर और लड़ाके कभी भी फिर से माहौल खराब कर सकते हैं। इनके पास अभी भी संसाधन हैं, लड़ाके हैं। जोसेफ की आशंका में दम है। अमेरिकी सेना आइएस की ताकत को समझती है। शुरुआती दौर में आइएस को अमेरिकी संरक्षण मिला था, अमेरिका इस फिराक में था कि आइएस के लड़ाके असद सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। अभी भी यही सवाल उठाए जाते हैं कि आइएस के पास अमेरिकी और इजरायली हथियार कहां से आए? आइएस के प्रमुख अबू बकर अल बगदादी अमेरिकी सैनिकों के कब्जे में रहा। तब फिर वह आइएस का मुखिया कैसे बन गया?

सीरिया में आइएस राज खत्म किए जाने को लेकर दावे जरूर हैं। लेकिन अभी भी सच्चाई यह है कि हजारों लड़ाके सीरिया और इराक के दूरदराज इलाकों में चुपचाप बैठ गए हैं। चूंकि इराक में भी आइएस के खात्मे का दावा दिसंबर 2017 में किया गया था। लेकिन दस महीने में ही इराक में एक हजार से ज्यादा आतंकी हमले इराके में हुए। यही खतरा सीरिया में है। यहां से बहुत सारे लड़ाके भाग कर एशिया के कुछ देशों में भी पहुंच गए हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आइएस के कमांडर मौजूद हैं। इसकी खबर रूस, अमेरिका और चीन को लंबे समय से है। अफगानिस्तान में आइएस के खतरे को भांपते हुए रूस ने तालिबान से बातचीत शुरू की थी और पाकिस्तान, चीन सारे देशों को तालिबान से बातचीत बढ़ाने को कहा था। अफगानिस्तान में आइएस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अमेरिका ने तालिबान से बातचीत तेज की। इस समय आइएस की खुरासान शाखा अफगानिस्तान में खासी सक्रिय है। पिछले दो-तीन साल में खुरासान शाखा ने अफगानिस्तान में खासा प्रभाव बढ़ाया है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार इस समय अफगानिस्तान में आइएस के ढाई हजार लड़ाके मौजूद हैं। पूर्वी अफगानिस्तान के ननगहार, कुनार सहित कुछ राज्यों में इनकी सक्रियात खासी है। काबुल तक में ये सक्रिय हैं। अफगान तालिबान के लड़ाके और कुछ कमांडर भी आइएस के साथ जुड़ गए। इन्हें पैसे के लोभ ने आइएस की तरफ मोड़ा। सीरिया और इराक के कई इलाकों के संसाधनों के कब्जे के बाद आइएस के पास खासा पैसा जमा हो गया। इस पैसे का इस्तेमाल आइएस अफगानिस्तान, फिलिपीन से लेकर पश्चिमी अफ्रीका तक कर रहा है।

अफगानिस्तान में आइएस के बढ़ते प्रभाव का अंदाजा बम धमाकों से लगाया जा सकता है। 2018 मे आइएस ने अफगानिस्तान में कई आत्ममघाती हमले किए। इसमें ढाई सौ के करीब लोग मारे गए। यही नहीं अफगानिस्तान का पड़ोसी शिया ईरान भी आइएस के हमले का शिकार हुआ है। सितंबर 2018 मे आइएस ने ईरान में एक सैन्य परेड पर हमला कर तीस ईरानी सैनिकों को मार डाला था। उधर पूर्वी एशिया के दो देश- इंडोनेशिया और फिलिपीन भी आइएस के शिकार हैं। आइएस यहां खासा सक्रिय है। वर्तमान में फिलिपीन में आइएस की गतिविधियां काफी तेज है। फिलिपीन में आइएस से संबंधित अबु सयाफ ग्रुप की सक्रियता ने पूर्वी एशिया में चिंता बढ़ाई है।

भारत में आइएस अपनी गतिविधियां फैलाने में सफल नहीं हो पाया है। भारत जैसे देश से आइएस सीरिया, इराक आदि देशों में जेहाद के लिए ज्यादा कैडर भी नहीं जुटा पाया। हालांकि कुछ युवा आइएस की विचारधारा से प्रभावित हो सीरिया, इराक और अफगानिस्तान के लिए गए, लेकिन इनकी संख्या सौ का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाई। लेकिन भारत के पड़ोसी पाकिस्तान और बांग्लादेश में आइएस की गतिविधियां बढ़ी हैं, इसमें कोई शक नही है। इससे भारत की चिंता बढ़नी लाजिमी है। जुलाई 2016 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका के एक रेस्तरां में आइएस के हमले ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। इस हमले में बीस लोग मारे गए थे, जिसमें एक भारतीय महिला भी थी। इस हमले ने साबित किया था कि आइएस बांग्लादेश में पैठ जमा चुका है। हालांकि बांग्लादेश की सरकार ने कट्टरपंथ से डट कर मुकाबला किया है। यहां कट्टरपंथियों की कमर भी तोड़ी गई है। लेकिन ढाका में कैफे के अंदर आतंकी हमले के बाद भारत सतर्क हो गया था। क्योंकि आइएस के ऑनलाइन जेहाद से देश के कुछ राज्यों के युवा आइएस से प्रभावित हो सीरिया, इराक और अफगानिस्तान तक पहुंच गए थे। कश्मीर में कई बार आइएस के झंडे लहराए गए। भारत की चिंता इसलिए भी बढ़ी कि अभी तक भारत को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से निपटना पड़ रहा है। लेकिन आइएस के प्रभाव अगर बढ़ा तो भारत की मुश्किलें और बढ़ेंगी। हालांकि भारतीय सुरक्षा तंत्र फिलहाल आइएस की गतिविधियों को नियंत्रण करने में सफल रहा है। भारत की चिंता यह भी है कि पड़ोसी देश म्यांमा की रोहिंग्या नीति पूर्वी एशिया में आइएस को घुसपैठ के लिए जमीन तैयार कर सकती है।

सीरिया में आइएस का अंत करने का दावा तो किया गया है, इसका मुखिया बगदादी कहां है, इसकी जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को नहीं है। पश्चिम एशिया में महाशक्तियों की नीतियों ने हमेशा से स्थानीय लोगों की समस्या बढ़ाई है। बशर अल असद की सरकार को खत्म कर अमेरिका सीरिया की गद्दी पर अपना मुखौटा बिठाना चाहता था, ताकि इराक से सीरिया के रास्ते भूमध्यसागर तक जाने वाले आर्थिक गलियारे पर अमेरिकी प्रभाव स्थापित हो जाए। इसलिए सीरिया में कई असद विरोधी आतंकी गुटों को अमेरिका हवा देता रहा। आइएस ने भी इसका फायदा उठाया। बाद में आइएस इतना ज्यादा मजबूत हो गया कि पूरे इलाके में अमेरिका और रूस के लिए भी चुनौती बन गया। आज अफगानिस्तान समेत मध्य एशिया के कई देशों में आइएस की बढती गतिविधियों से चीन, रूस भी परेशान है। तभी अफगान तालिबान को रूस ने अपने प्रयास से शांति वार्ता की मेज पर लाने की कोशिश की। मास्को में तालिबान के साथ बैठक आयोजित की गई। अमेरिका भी आइएस के आसन्न खतरे को देख रहा है। तभी तालिबान से कई दौर की शांति वार्ता हो चुकी है।

आइएस के बढ़ते प्रभाव से चीन चिंतित है। पाकिस्तान और मध्य एशिया के देशों में चीन सौ अरब डालर से ज्यादा का निवेश कर चुका है। इसलिए आइएस की मजबूती चीन के लिए खतरा बन सकती है। आइएस की मजबूती से पश्चिमी चीन में सक्रिय उइगुर अलगाववादियों का मनोबल बढ़ेगा। इसलिए चीन किसी कीमत पर आइएस की मजबूती नहीं चाहेगा। दरअसल आइएस चीन के प्रस्तावित बेल्ट एंड रोड पहल के लिए भारी खतरा है।

दरवाजे के आर-पार

तनिष्का वैद्य

दुनिया मेरे आगे

कुछ समय पहले राजस्थान जाना हुआ तो वहां के दरवाजों ने मुझे बहुत आकर्षित किया। वे दरवाजे कुछ अलग-से थे। कुछ बहुत रंगीन थे और उन पर राजा, रानी, दरबारियों और ऊंट, हाथी, घोड़े को उकेरा गया था। वे बहुत पुराने थे, शायद राजा-रानी के समय के और उनके नाम भी उसी समय के थे। जैसे, सूरज पोल, चांद पोल, त्रिपोलिया दरवाजा आदि। वहां से लौटने के थोड़े दिनों बाद दक्षिण भारत जाने का मौका मिला और जब उन इलाकों में दरवाजों को देखा तो वे राजस्थान के दरवाजों से बिल्कुल अलग थे। वहां लकड़ी के दरवाजों पर चिह्न उकेरे गए थे जो आसपास फैली प्रकृति को दर्शा रहे थे।

दरअसल, हमारे देश के लगभग हर प्रांत में दरवाजों का एक नया स्वरूप देखने को मिलता है। मनुष्य की सभ्यता के शुरुआती दौर में भी गुफाओं में रहने वाले आदिमानव दरवाजों के रूप में बड़े-बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया करते थे। जैसे-जैसे समय बदला, दरवाजों का रूप भी बदलता गया। पहले लोहे के भारी-भरकम दरवाजे होते थे। बाद में हल्के दरवाजे बनाने के लिए लकड़ी का उपयोग होना शुरू हुआ। आज भी हमें कई जगह बड़े-बड़े लोहे के दरवाजे नजर आते हैं। पुराने किलों में लगे दरवाजों को खोलने के लिए कई सैनिक हुआ करते थे। तब बहुत बड़े दरवाजे बनाए जाते थे, ताकि बाहरी इलाकों से आए कोई समूह या अन्य राज्यों या देशों की सेनाएं आक्रमण करें तो वे सीधे महल में नहीं दाखिल हो पाएं। उन दरवाजों को रक्षक दीवार का हिस्सा भी कहा जा सकता है।

लेकिन इससे इतर देखा जाए तो दरवाजा हमारे रोजमर्रा के जीवन का अहम हिस्सा हैं। मगर अक्सर हम इसके महत्त्व को भूल जाते हैं। दरवाजा ही दुनिया के लिए हमारे रास्ते खोलता है। ये हमेशा हमें नए रास्ते दिखाते हैं। दरवाजे सिर्फ हमें बाहर की दुनिया से ही परिचित नहीं कराते, बल्कि वे हमारे घर के भीतर तक भी ले जाते हैं। ये हमारे घर को दुनिया से अलग करते हैं। ये हमारी संस्कृति, कला और इतिहास को भी दर्शाते हैं। कई बार दरवाजों से मकान की उम्र पता चल जाती है। हर दरवाजा उस जगह की कहानी सुनाते किस्सागो की तरह होता है।

मुख्य दरवाजों को ऊर्जा का चिह्न माना जाता है। इनके बारे में अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग मान्यताएं हैं। कहीं उन्हें सभी दरवाजों से बड़ा बनाया जाता है तो कहीं उन पर अलग-अलग चिह्न उकेरे या बनाए जाते हैं। हर जगह दरवाजों पर कुछ अलग देखने को मिलता है। वे ज्यादातर सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं, ताकि कोई भी सीधे घर में नहीं घुस सके। इस तरह वे घर को दुनिया से अलग करते हैं।

अगर अध्ययन के लिहाज से देखें तो आमतौर पर घरों की परंपरा और संस्कृति उसके दरवाजे से ही पता चल जाती है। कह सकते हैं कि दरवाजों पर संस्कृति की छाप होती है। लेकिन समय के साथ-साथ हमारे घरों के दरवाजे और उनकी सजावटें भी बदल गई हैं। नई बसाहटों में आजकल सभी घरों के दरवाजे लगभग एक से होते हैं। घर के मुख्य दरवाजे पर अब पुरानी परंपराएं और संस्कृति के निशान या उनकी छवियां भी देखने को नहीं मिलती। दरवाजों के बंद होने के कारण उन पर पहले की तरह अब व्यस्तताओं की वजह से ध्यान नहीं दिया जाता। जहां कभी दरवाजे घर की शान होते थे, वहीं आजकल छोटे घरों के चलन में दरवाजे भी छोटे हो गए हैं। जो दरवाजे हमें सदियों तक दुनिया से जोड़ते रहे, वे आजकल ज्यादातर बंद ही रहते हैं। दिनोंदिन बढ़ रहे गुनाहों का खमियाजा दरवाजों को दिन भर बंद रह कर चुकाना पड़ रहा है।

दरवाजे दुनिया में झांकने का जरिया हैं। दरवाजों के भीतर घर में बैठे लोगों के लिए वह उनकी छोटी-सी दुनिया होती है, जिसमें सिर्फ उनका परिवार होता है। दरवाजे हमारे घर की बात को बाहर नहीं जाने देते हैं। वे घर का मान बढ़ाते हैं। सूरज की रोशनी और हवा भी इन्हीं से हमारे घर में आती है, जिससे घर का वातावरण सुखद रहता है।

दरवाजे हमें दुनिया से मिलाते हैं। इन्हें खोल कर हम बाहर की दुनिया से रूबरू होते हैं। ये हमारे लिए ज्ञान और सफलता के रास्ते खोलते हैं। इनसे गुजर कर ही हम बाहर की दुनिया को जान पाते हैं और कुछ नया सीख पाते हैं। दरवाजा हमें दुनिया से मिलाता भी है तो अलग भी करता है। हर दरवाजे के अंदर और बाहर दो अलग दुनिया होती है और दोनों एक दूसरे से विपरीत। अगर घर के दरवाजे खुले हों तो हमारी सेहत को ठीक रखते हैं, अगर दिमाग के दरवाजे खुले हों तो ज्ञान। सफलता और अवसरों की सौगात अपने आप दे जाते हैं और अगर दिल के दरवाजे खुले हों तो बहुत आसानी से दुनिया को जीता जा सकता है।

लोकपाल की शक्तियां

भारत के राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को देश का पहला लोकपाल नियुक्त किया है। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के आने के लगभग पांच साल बाद लोकपाल का गठन हो पाया। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 और लोकपाल के व्यावहारिक गठन, दोनों के लिए ही राजनीतिक इच्छाशक्ति का भारी अभाव रहा। व्यापक आंदोलन के बाद वर्ष 2013 में अधिनियम आया और संसद ने उसमें भी कई बार संशोधन किए, किंतु अंत में सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद लोकपाल का गठन हो पाया।

जाहिर है, राजनीतिक इच्छाशक्ति किसी भी संस्था की सफलता के लिए धुरी का कार्य करती है। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के आने के बाद विभिन्न राज्यों ने लोकायुक्तों का गठन किया, किंतु अभी तक संबंधित राज्यों में भ्रष्टाचार में कमी नहीं आई है। बड़े पदों पर बैठे अधिकारियों या मंत्रियों द्वारा भ्रष्टाचार में कमी आने की बात तो दूर, बल्कि इनके भ्रष्टाचार में बढ़ोत्तरी हुई है। केंद्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए सीबीआइ, सीवीसी, ईडी जैसी एजेंसियां तो हैं और न्यायालय भी इसमें अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार देश के प्रशासनिक ढांचे में जड़ जमाए बैठा है।

इस स्थिति में लोकपाल से बहुत ज्यादा उम्मीद उचित प्रतीत नहीं होती है। इसके अलावा अन्य भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाओं की तरह लोकपाल को भी पर्याप्त शक्तियां नही दी गई हैं जिससे यह व्यावहारिक धरातल पर दंतहीन-नखहीन व्याघ्र और विषहीन सर्प की तरह साबित हो सकता है।

● *वीर सिंह, जालौन*

सत्ता का लालच

जम्मू-कश्मीर में पीडीपी और नेशनल कांफ्रेंस के नेताओं ने धारा-370 के मामले में जो बयान दिए हैं, वे बेहद निंदनीय है। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि हम जिस देश की मिट्टी में पैदा हुए हैं वहां का सम्मान करना चाहिए और देश का संस्कृति और मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। लेकिन उमर अबदुल्ला, महबूबा मुफ्ती जैसे नेता अपने ही देश को तोड़ने की बातें कर रहे हैं। वोट की राजनीति और सत्ता के लालच में वे भूल चुके हैं कि वे कैसे-कैसे बयान दे रहे हैं। पिछले एक-दो सालों में तो यह और भी बढ़ गया है। इन नेताओं का एक भी बयान ऐसा नहीं है जो उनके भारत देश के प्रति प्रेम को दर्शाता हो। वहां की जनता को चाहिए कि ऐसे नेताओं को चुनाव में सबक सिखाए जो सत्ता के लिए देश को विभाजित करने की बातें करते हैं।

● *शुभम गुप्ता, धनबाद*

अमल की चुनौती

कांग्रेस द्वारा घोषित गरीबों को न्यूनतम आय देने की योजना बहुत बड़ी योजना है। इस योजना के तहत करीब पांच करोड़ परिवार और पांच करोड़ परिवारों को 72000 रुपए की न्यूनतम आय दिए जाने की घोषणा की है। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर योजना लागू किया जाता है तो इससे सरकारी खजाने पर हर साल 3.6 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। यह अगले वित्त वर्ष यानी 2019-20 के लिए तय कुछ 27, 84, 200 करोड़ रुपए के बजट का करीब तेरह फीसद है। यह भारत की कुल जीडीपी का करीब दो फीसद हिस्सा होगा। वैसे तो यह योजना लागू तब होगी जब कांग्रेस सत्ता में आती है। लेकिन वास्तव में यह योजना दुनिया की सबसे बड़ी कल्याणकारी योजना साबित हो सकती है। जानकारों का मानना है कि इस योजना को लागू करने के लिए राजस्व जुटाने के वैकल्पिक स्रोत तलाशने होंगे।

● *सुधीर यादव, गोरखपुर*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

घोषणाएं समाधान नहीं

लोकतंत्र के इस महापर्व के अवसर पर सभी राजनीतिक दल घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। सवाल है कि क्या वाकई में इन राजनीतिक दलों के पास देश की समस्याओं का हल है, जिससे आम जनता को परेशानियों से निजात मिल सके। कांग्रेस ने अपना लोकलुभावना घोषणापत्र जारी कर दिया है, अन्य दल भी कर रहें है। लेकिन लगता नहीं है कि इन घोषणाओं से देश का कल्याण होगा, क्योंकि चुनाव के बाद सारी घोषणाएं हवा हो जाती हैं। बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ते अपराध, संकट से जूझते किसान, महिला सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि ऐसे मुद्दे हैं कि इन समस्याओं का हल वातानुकूलित कमरों में बैठने वालों के पास नहीं है। इन समस्याओं का उचित हल इन कार्यों से जुड़े हुए लोगों के पास ही हो सकता है। जब तक घोषणापत्र बनाने वाली समिति में बैठे लोग जमीनी हकीकत कोनहीं देखेंगे तब तक इन समस्याओं का कोई हल नहीं निकल सकता है।

● *राम रैबारी, जोधपुर*

गंगा की निर्मलता

अमृतमयी गंगा नदी का जल लगातार प्रदूषित हो रहा है। धीरे-धीरे इसका पानी जहरीला होता जा रहा है। इसके लिए और कोई नहीं, भारतवासी ही जिम्मेदार हैं। औद्योगिक इकाइयों के जहरीले रसायन प्रतिदिन गंगा में प्रवाहित हो रहे हैं। जिससे यह पवित्र नदी गंदे नाले का रूप लेती जा रही है। प्रदूषित होकर गंगा अपनी मूल पहचान खोती जा रही है। लोक हित में गंगा को साफ रखना बेहद जरूरी है। गंगा को प्रदूषित कर रही औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। गंगा किनारे पर बसे नगरों के गंदे नालों का पानी इसमें मिलने से रोकना होगा। नदी को लगातार साफ रखने के लिए इसमें कचरा बिल्कुल न फेंका जाए, इसके लिए जनभागीदारी भी अतिमहत्त्वपूर्ण है।

● *राजेंद्र कुमावत, जयपुर*

मुफ्त का चंदन

कर्जमाफी, कृषक सम्मान निधि, बिना काम बहत्तर हजार रुपए, पेंशन योजनाओं आदि के बाद बाईस लाख रोजगार और मनरेगा की जरूरत ही क्या रह जाती है? मतदाता के मानस की पहचान कांग्रेस के इस मास्टरस्ट्रोक से मिलती है कि उन्हें अपने स्वार्थों की चिंता है, देश की नहीं। किसी ने भी यह प्रतिक्रिया नहीं दी कि हमें खैरात का ऐसा पैसा नहीं चाहिए, लेकिन देश के आधारभूत ढांचे, सड़क-रेल, पेय-सिंचाई व भूमिगत जल संवर्धन परियोजनाएं, प्राकृतिक ऊर्जा स्रोतों का दोहन, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास व सशक्तिकरण की नई-पुरानी परियोजनाओं आदि में धन की कमी नहीं होनी चाहिए।

● *राधेश्याम ताम्रकर, इंदौर*